दैनिक भारत कि
तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com
Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-२ ला | अंक-७१ वा | सोमवार १५ दिसंबर २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

घोषणाओं की बाढ़ में किसानों के साथ-साथ विपक्ष भी ठगा!

नागपुर में हुए शीतकालीन अधिवेशन से अतिवृष्टि के कारण हुए अभूतपूर्व किसान नुकसान, सामने आए भ्रष्टाचार के मामले और राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं से बिगड़ी कानून-व्यवस्था पर महायुति सरकार ठोस कदम उठाएगी-ऐसी उम्मीद लगाए बैठे किसानों (बळीराजा) के हिस्से में केवल घोषणाओं की बरसात ही आई। भारी बहुमत वाली सरकार इस अधिवेशन में भी विपक्ष को संवैधानिक रूप से विपक्ष के नेता का पद देने का सौजन्य नहीं दिखा सकी। नतीजतन, केवल बातें और औपचारिकता निभाते हुए उपराजधानी में अधिवेशन संपन्न कर दिया गया।

शीतकालीन अधिवेशन डायरी

- जमीर काझी

सिर्फ सात दिन चले इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य ७५ हजार करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगों को मंजूरी देना ही रहा, यह सामने आया है। अल्प संख्याबल वाली महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने भी इसी पर खेद जताया।

अधिवेशन से न किसानों को कुछ मिला, न ही विदर्भ की जनता को-इसलिए यह अधिवेशन निष्फल रहा, ऐसी तीखी आलोचना विपक्ष ने अधिवेशन समाप्त होने के बाद संयुक्त पत्रकार परिषद में की।

विधानसभा में एक वर्ष से और विधान परिषद में चार महीनों से विपक्ष का नेता नहीं है, जिससे विपक्ष पहले से ही कमजोर स्थिति में था। सजग लोकतंत्र में राज्य की समस्याएं प्रभावी ढंग से उठाने और उनके अनुवर्तन के लिए विपक्ष के नेता का पद आवश्यक माना जाता है। लेकिन सत्ताधारियों का इरादा विपक्ष को जड़ से खत्म करने का दिख रहा है। मुंबई सहित राज्य की २९ महानगरपालिकाओं और २४ जिला परिषदों के चुनाव सामने होने के कारण यह संवैधानिक पद देकर विपक्ष को आसान बढ़त नहीं दी जाएगी-यह स्पष्ट हो गया है। इसी कारण विपक्ष के लगातार आग्रह के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उनकी इच्छा हो भी तो 'देवाभाऊ' की हरी झंडी के बिना यह संभव नहीं-इसलिए केवल विचार करेंगे का आश्वासन देकर समय टाला गया। किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं को रोकने या विदर्भ के लिए एक भी नई घोषणा नहीं हुई; केवल आगामी महानगरपालिका चुनावों को ध्यान में रखकर अधिवेशन की औपचारिकताएं पूरी की गईं-ऐसा कहना पड़ेगा।

विदर्भ के धान, सोयाबीन और कपास उत्पादक किसान इस अधिवेशन की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे थे। धान और सोयाबीन पर बोनस की मांग की गई, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। राज्य के युवाओं को नशे की समस्या जकड़े हुए है, पर उस पर भी सरकार की कोई ठोस कार्ययोजना नहीं है-यह आलोचना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के समूह नेता भास्कर जाधव, कांग्रेस विधिमंडल नेता विजय वडेट्टीवार, विधान परिषद के समूह नेता सतेज पाटील, नाना पटोले, राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के नेता जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे और सचिन अहीर ने की।

राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरदचंद्र पवार) के नेता जयंत पाटील ने कहा कि मुख्यमंत्री निवेश आने की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता में निवेश नहीं हुआ है; इसलिए बेरोजगारी की समस्या भी नहीं सुलझी। विपक्ष द्वारा उठाए गए कानून-व्यवस्था के सवालों पर भी ठोस जवाब नहीं मिला। नतीजतन, सात दिनों में जनता के हिस्से में केवल निराशा ही आई-ऐसी तीखी टिप्पणी जयंत पाटील ने की।

महाराष्ट्र का विकास अब नहीं रुकेगा-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

राज्य के रचनात्मक कार्य के लिए एकजुट होने का आह्वान, शीतकालीन अधिवेशन संपन्न

जमीर काज़ी

नागपुर, १४ दिसंबर (रिपोर्टर)

महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था देश में सबसे अधिक सशक्त और स्थिर है तथा सभी आर्थिक मानकों पर राज्य खरा उतरता है। कर्ज, राजकोषीय घाटा, निवेश, रोजगार सृजन, सिंचाई, बिजली, परिवहन और कानून-व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में राज्य ने ठोस कार्य किया है। विदर्भ का विकास तेज़ी से होगा और जब तक सूर्य-चंद्र रहेंगे, तब तक महाराष्ट्र से मुंबई को कोई अलग नहीं कर सकता-यह स्पष्ट शब्दों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा।

शीतकालीन अधिवेशन के दौरान विधानसभा में नियम २९३ के तहत प्रस्तुत अंतिम सप्ताह प्रस्ताव पर उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने लगभग दो घंटे का भाषण दिया और सभी पहलुओं की विस्तार से समीक्षा रखी।

इस बीच शीतकालीन अधिवेशन संपन्न हो गया है। अगले वर्ष का बजट सत्र २३ फरवरी से मुंबई में आयोजित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद सामने आई विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए निर्णयक्षमता और समन्वय के साथ शासन चलाया जा रहा है। अब इन सबको पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अमृत महोत्सवी महाराष्ट्र के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते हुए सदन के सभी सदस्यों से रचनात्मक कार्य के माध्यम से राज्य की प्रगति के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने सकारात्मकता और विकास-केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा, अब आगे बढ़ चुका हूं मैं अब कदम रुकने वाले नहीं, और स्पष्ट किया कि विकास के मार्ग पर राज्य की प्रगति नहीं थमेगी।

मुंबई को लेकर स्पष्ट रुख रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई महाराष्ट्र की थी, है और हमेशा रहेगी। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में १०६ शहीदों के बलिदान से महाराष्ट्र का निर्माण हुआ है, इस पर किसी भी प्रकार का भ्रम रखने की आवश्यकता नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज और भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा दिखाए गए मार्ग पर, संविधान की चौखट के भीतर महाराष्ट्र आगे बढ़ता रहेगा।

उन्होंने बताया कि २०४७ तक विकसित महाराष्ट्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और २०२९-३० के दौरान देश की पहली ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र की होगी-इस दिशा में कार्य शुरू है।

राज्य सरकार की योजनाओं के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि 'लाडकी बहन' योजना, किसानों के लिए मुफ्त बिजली सहित सभी योजनाएं जारी हैं और अगले पांच वर्षों तक जारी रहेंगी।

राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बताते हुए उन्होंने कहा कि बड़े राज्यों की तुलना में आज भी सभी मानकों पर महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था मजबूत है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के २५ प्रतिशत तक कर्ज लेने की अनुमति है, जबकि महाराष्ट्र ने केवल १८.८७ प्रतिशत कर्ज लिया है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि उद्योग, निवेश, रोजगार सृजन, ऊर्जा, कृषि और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में महाराष्ट्र ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं और देश में सर्वांगीण विकास का आदर्श प्रस्तुत किया है। निवेश के मामले में केवल समझौते नहीं, बल्कि उनका क्रियान्वयन भी हो रहा है। दावोस में हुए १७ लाख ५७ हजार ८०१ करोड़ रुपये के समझौतों में से ७५ प्रतिशत पर अमल शुरू हो चुका है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में महाराष्ट्र देश में अव्वल है। वर्ष २०२४-२५ में रिकॉर्ड १ लाख ६४ हजार ७७५ करोड़ रुपये का निवेश आया, जो देश के कुल निवेश का ३१ प्रतिशत है। वर्ष २०२५-२६ में अब तक ९१,३३७ करोड़ रुपये का एफडीआई महाराष्ट्र में आ चुका है।

विदर्भ और मराठवाड़ा में निवेश का प्रवाह

मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों के लिए घोषित ३२ हजार करोड़ रुपये के पैकेज में से १५ हजार ७ करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में जमा किए गए हैं। रबी मौसम के लिए घोषित १० हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता ९१ लाख किसानों को मिली है। कपास खरीद में किसानों को नुकसान न हो, इसके लिए औसत उत्पादकता १,२७७ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर २,३६८ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करने का निर्णय लिया गया है।

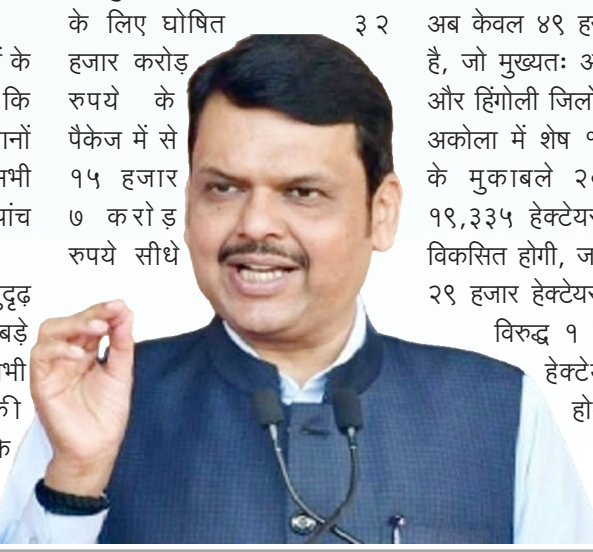

कर्जमाफी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि निर्णय लिया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए समिति गठित की गई है कि कर्जमाफी का लाभ सीधे किसानों को मिले, बैंकों को नहीं। समिति की रिपोर्ट आने के बाद १ जुलाई तक कर्जमाफी की योजना और नीति तय की जाएगी।

विदर्भ और मराठवाड़ा में १३ लाख ८३ हजार हेक्टेयर का सिंचाई बैकलॉग लगभग समाप्त हो चुका है। इंडिकेटर बैकलॉग समिति द्वारा निर्धारित इस बैकलॉग में से १३ लाख ३४ हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है और अब केवल ४९ हजार हेक्टेयर शेष है, जो मुख्यतः अकोला, बुलढाणा और हिंगोली जिलों तक सीमित है। अकोला में शेष १४,५३० हेक्टेयर के मुकाबले २०२६-२७ तक १९,३३५ हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित होगी, जबकि बुलढाणा में २९ हजार हेक्टेयर के बैकलॉग के विरुद्ध १ लाख ६८ हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा।

नागपुर-गोवा शक्ति पीठ एक्सप्रेसवे से यात्रा समय घटकर आठ घंटे रह जाएगा, जिससे मराठवाड़ा की तस्वीर बदलेगी। साथ ही प्रस्तावित मुंबई-कल्याण-लातूर जन कल्याण एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है, जिससे लातूर से मुंबई की यात्रा मात्र ४.५ घंटे में संभव होगी।

गृह विभाग पर चर्चा का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य की कानून-व्यवस्था से जुड़े आंकड़े प्रस्तुत किए। अक्टूबर २०२४ से अक्टूबर २०२५ के बीच पुणे में अपराधों में कमी आई है। नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद दोषसिद्धि दर बढ़कर ९६.२४ प्रतिशत तक पहुंची है। डायल ११२ सेवा का प्रतिक्रिया समय १५ मिनट से घटकर लगभग ७.३७ मिनट हो गया है।

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर उन्होंने बताया कि शिकायत दर्ज करने की दर ९९ प्रतिशत से अधिक है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में ६० दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की दर अक्टूबर २०२५ तक बढ़कर ८७.८ प्रतिशत हो गई है।

महासाइबर देश का सबसे आधुनिक साइबर मुख्यालय बन चुका है और कई राज्यों तथा दो देशों ने सहयोग के लिए अनुरोध किया है। नशीले पदार्थों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति लागू है और पेडलरों पर मकोका व एमपीडीए के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पिछले दस वर्षों में ८८ हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी-यह भरोसा भी मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया।

▶▶पान

यात्रियों के लिए आरामदायक बसें, लेकिन कर्मचारियों के वेतन का सवाल अब भी हवा में

बीड (रिपोर्टर)

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एस.टी.) ने यात्रियों के लिए शिवाई, शिवशाही और इलेक्ट्रिक बसों जैसी अत्याधुनिक सेवाएं शुरू कर सार्वजनिक परिवहन के स्तर को ऊंचा किया है। ऑनलाइन आरक्षण, सुसज्जित बस स्टैंड, आरामदायक सीटें और आधुनिक तकनीकी सुविधाओं के कारण यात्रियों को बड़ी राहत मिल रही है। हालांकि, इस चमक-दमक के पीछे एस.टी. की रीढ़ माने जाने वाले चालक-परिचालक और यांत्रिक कर्मचारियों के कई बुनियादी प्रश्न आज भी लंबित हैं, यह हकीकत सामने आ रही है।

कर्मचारी संगठनों के अनुसार लंबित वेतन और बकाया राशि का मुद्दा सबसे गंभीर है। समय पर वेतन न मिलने से कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। इसके साथ ही लंबी दूरी की ड्यूटी के दौरान आवश्यक आवास और विश्राम की व्यवस्था बेहद अपर्याप्त है। कई डिपो के विश्रामगृह जर्जर हालत में हैं और कुछ स्थानों पर ठहरने के लिए मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। अत्याधुनिक बसें लाई गईं, लेकिन उन्हें चलाने वालों के लिए आधुनिक आवास कब? ऐसा सवाल कर्मचारी वर्ग उठा रहा है।

काम के लंबे घंटे, अपर्याप्त विश्राम और सुरक्षा संबंधी समस्याओं के कारण तनाव बढ़ रहा है, जिसका असर यात्री सुरक्षा पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वार्षिक वर्दी, जूते, चिकित्सा जांच और सुरक्षा उपकरण जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नियमित रूप से न मिलने की शिकायतें हैं। कुछ मार्गों पर रात के समय पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और पुलिस सहायता न होने की बात भी कर्मचारियों ने कही है।

यात्रियों की सुविधा के लिए नई बस सेवाएं शुरू करना निश्चित रूप से सकारात्मक कदम है, लेकिन जब तक इन सेवाओं को चलाने वाले कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित सेवा बनाए रखना संभव नहीं होगा, ऐसा संगठनों का स्पष्ट मत है। एस.टी. प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की जा रही है कि यात्री सुविधाओं के साथ-साथ चालक-परिचालकों के वेतन, आवास, कार्य समय और सुरक्षा के मुद्दों पर तुरंत ध्यान दिया जाए।

महिलाओं के लिए बने विश्रामगृह केवल नाम के हैं, वहां आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं और मजबूरी में महिलाओं को वहां ठहरना पड़ता है। ड्यूटी लगाते समय परिपत्रों का पालन नहीं किया जाता और रात दस-दस बजे तक महिलाओं की ड्यूटी लगाई जाती है। हर डिपो में महिलाओं के लिए अलग रोटेशन व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा ज्योति ओव्हाळ ने कहा।

सरकारी कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता (डीए) नहीं दिया जाता। ग्रामीण क्षेत्रों में ठहरने वाले कर्मचारियों को गांवों में विश्रामगृह की सुविधा नहीं मिलती। बसों में चालक-परिचालकों के लिए सोने की अलग व्यवस्था नहीं है। लगभग ४४ हजार करोड़ रुपये की कर्मचारियों की बकाया राशि तुरंत दी जाए, ऐसी मांग की गई है। टिकट दरें एक रुपये के अंतर में होने से परिचालकों को परेशानी होती है, इसलिए उन्हें पांच रुपये के अंतर में किया जाए। केवल किलोमीटर पूरा करने के लिए खाली बसें भेजने की बजाय जहां यात्री अधिक हों वहीं बसें भेजी जाएं। बस स्टैंड सुधारे गए हैं, लेकिन कई डिपो की हालत दयनीय है। आरटीओ द्वारा लगाए गए एक हजार रुपये के जुर्माने माफ किए जाएं। मैकेनिक कर्मचारियों को समय पर स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते और खराबी होने पर उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

जिलाध्यक्ष चातुर ज्ञानेश्वर ने बताया कि संगठन के महासचिव श्री ताटे और अध्यक्ष श्री संदीप शिंदे कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री सहित भाजपा व शिवसेना (शिंदे गुट) के मंत्री-विधायकों ने आरएसएस मुख्यालय को किया नमन

अजित पवार के विधायकों की इस वर्ष भी रही अनुपस्थिति

जमीर काज़ी

नागपुर (रिपोर्टर)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना (शिंदे गुट) के मंत्रियों व विधायकों ने रविवार सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के मुख्यालय का दौरा किया। सभी ने सरसंघचालकों की समाधि के दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार, विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन के लिए नागपुर आने वाले भाजपा और शिवसेना के मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री और पदाधिकारी आरएसएस के डॉ. हेडगेवार स्मृति मंदिर में दर्शन करते हैं और संघ के विचारों से अवगत होते हैं। हालांकि, इस वर्ष बौद्धिक सत्र का आयोजन नहीं किया गया।

रेशीमबाग स्थित स्मृति मंदिर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित सभी नेताओं ने सरसंघचालकों की समाधि के दर्शन किए और नतमस्तक होकर अभिवादन किया। इसके पश्चात महर्षि व्यास सभागृह के नीचे भूतल स्थित हॉल में सभी नेताओं के लिए चाय-पान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साथ बैठकर कॉफी पी और उसके बाद दोनों एक साथ बाहर निकले।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्ववादी विचारधारा पर आधारित संगठन है और शिवसेना भी प्रखर हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला दल है।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

सर सैयद अहमद खान एवं पीपल्स हाई स्कूल, बीड में भव्य इस्लामिक प्रदर्शनी का आयोजन

बीड, १२ दिसंबर २०२५

सर सैयद अहमद खान एंड पीपल्स हाई स्कूल, बीड की ओर से एक भव्य इस्लामिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बीड शहर एवं आसपास के क्षेत्र के अनेक प्रसिद्ध, प्रभावशाली और सम्माननीय इस्लामिक धर्मगुरुओं ने विशेष रूप से उपस्थित रहकर इस प्रदर्शनी की शोभा बढ़ाई। विद्यालय प्रबंधन और विद्यार्थियों ने अतिथियों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया।

प्रदर्शनी में इस्लामिक इतिहास, पैगंबर मोहम्मद (स.अ.व.) का जीवन चरित्र, खलीफाए-राशिदीन, इस्लामिक कला, सुलेखन, कुरआनी आयतों की कैलीग्राफी के माध्यम से प्रस्तुति तथा इस्लामिक सांस्कृतिक विरासत जैसे विविध विषयों पर तैयार किए गए मॉडल और चार्ट्स विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत कलात्मकता और शोधपूर्ण प्रस्तुति ने दर्शकों की भरपूर प्रशंसा प्राप्त की।

प्रमुख धर्मगुरुओं ने विद्यार्थियों के परिश्रम की सराहना करते हुए कहा कि, ऐसे कार्यक्रम नई पीढ़ी में धार्मिक जागरूकता उत्पन्न करते हैं और उन्हें अपनी संस्कृति व धर्म से जोड़ने का यह एक श्रेष्ठ माध्यम है।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुफ्ती अब्दुल्ला खासमी साहब ने की। प्रमुख अतिथियों में डॉ. फिरोज साहब, मौलाना शकील कासमी साहब, मुफ्ती आरिफ साहब मजहारी, मुफ्ती मोहसिन साहब, मुफ्ती अब्बास साहब, मौलाना मुख्तार साहब, मौलाना अब्दुल हादी साहब, मौलाना फुरखान साहब, हाफिज सोहेल साहब तथा डॉ. परवेज साहब शामिल थे। बड़ी संख्या में अभिभावकों, नागरिकों और विशेष आमंत्रितों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर विद्यालय के इस प्रयास की सराहना की। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एवं कलात्मक मॉडलों की सर्वत्र प्रशंसा हुई।

कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के हाफिज ज़ीशान साहब द्वारा इस प्रदर्शनी के लिए किए गए परिश्रम की विशेष रूप से सराहना की गई। विद्यालय के सचिव शेख अब्दुल वाकिल सर ने सभी अतिथियों और शिक्षकों का अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए आभार व्यक्त किया।

बीड शहर की अग्निशमन व्यवस्था पिछले २१ दिनों से पूरी तरह ठप

बीड : बीड शहर की आबादी लगभग चार लाख है। यहां न्यूनतम ८ अग्निशमन वाहन होने आवश्यक हैं। लेकिन केवल दो वाहनों से काम चलाया जा रहा है। इनमें से एक वाहन दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होने के कारण पिछले २१ दिनों से थाने में खड़ा है। वहीं दूसरा पंप खराब होने की वजह से पिछले ४४ दिनों से शोरूम में पड़ा हुआ है। बीड शहर में यदि आग लग जाए तो नगरपालिका के पानी के टैंकर को बुलाया जाता है। अगर शहर में कोई बड़ी आग की दुर्घटना होती है तो बीड की अग्निशमन व्यवस्था को हाथ पर हाथ धरे बैठना पड़ेगा।

बीड शहर का तेजी से विस्तार हुआ है, जिससे जनसंख्या और बस्तियां बड़े पैमाने पर बढ़ी हैं। इसके मुकाबले नगरपालिका के पास कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। आग बुझाने के लिए बीड जिले

की सबसे बड़ी नगरपालिका को दूसरी नगरपालिकाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। पिछले एक साल में बीड क्षेत्र में कुल १०५ आग की घटनाएं हुई हैं, जिन्हें नगरपालिका के वाहनों से बुझाया गया है।

किशोर जाधव, अग्निशमन अधिकारी : पंप की मरम्मत पर चार लाख रुपये का खर्च आएगा। इसके लिए नगरपालिका के पास निधि नहीं है। राशि बड़ी होने के कारण प्रशासकीय मंजूरी लेनी पड़ती है। लेकिन आचार संहिता के कारण यह प्रक्रिया रुकी हुई थी। अभी भी आचार संहिता लागू है। २०१२ में बीड अग्निशमन दल में शामिल किया गया ५ हजार लीटर क्षमता वाला वाहन का पंप खराब होने से ४ नवंबर २०२५ को बीड शहर के टाटा शोरूम में मरम्मत के लिए भेजा गया है। यह पंप इंदौर और सोलापूर में मिलता है। इसके लिए नगरपालिका ने चार कंपनियों से कोटेशन मंगवाए हैं। लेकिन अभी तक निधि नहीं मिलने से यह वाहन ४४ दिनों से शोरूम में पड़ा हुआ है।

प्रश्न : आग लगने पर कैसे बुझाई जाएगी?

उत्तर : पानी के टैंकर को कॉल किया जाता है। गेवराई और शिरूर नगरपालिका को पत्राचार किया गया है। उनके वाहन आपातकाल में उपलब्ध रहते हैं।

प्रश्न : महीने भर से वाहन क्यों बंद हैं?

उत्तर : एक वाहन दुर्घटना के कारण पुलिस थाने में है। दूसरा पंप मरम्मत के लिए शोरूम भेजा गया है।

प्रश्न : व्यवस्था पर्याप्त है क्या?

उत्तर : बढ़ती जनसंख्या के अनुसार मानवबल और यंत्रणा अत्यंत अपर्याप्त है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन कल पुणे मरम्मत के लिए भेजा जाएगा।

शिष्यवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के साथ संतुलन बनाए रखने का सरकार का प्रयास-अजित पवार

नागपुर (रिपोर्टर)

टीआरटीआई, बार्टी, सारथी, महाज्योती और अमृत जैसी स्वायत्त संस्थाओं के माध्यम से गुणवत्ताधारक विद्यार्थियों को शिष्यवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इन अधिछात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद और वंचित वर्गों के विद्यार्थियों तक पहुंचे, यही महायुति सरकार का उद्देश्य है। इसके लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, उचित मानकों के साथ निर्धारित दिशानिर्देश तय किए जाएंगे, ऐसी जानकारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने विधानसभा में दी।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने यह भी स्पष्ट किया कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों से आने वाले, विदेश में शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ विद्यार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता देना सरकार का उद्देश्य है। बार्टी की शिष्यवृत्ति के संबंध में विधानसभा सदस्य डॉ. नितिन राउत द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से टीआरटीआई, बार्टी, सारथी, महाज्योती और अमृत जैसी स्वायत्त संस्थाओं के माध्यम से दी जा रही शिष्यवृत्तियों का लाभ कुछ स्थानों पर एक ही परिवार के एक से अधिक विद्यार्थियों को मिल रहा है, ऐसी शिकायतें शासन को प्राप्त हुई हैं। इस संदर्भ में जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया जारी है। वर्तमान में इन शिष्यवृत्तियों पर इन संस्थाओं के कुल बजट का आधे से अधिक हिस्सा खर्च हो रहा है। इससे अन्य जरूरतमंद विद्यार्थियों की योजनाओं के लिए निधि की उपलब्धता प्रभावित न हो, इसके लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

इन स्वायत्त संस्थाओं के वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी देने के विषय पर मंत्रिमंडल की बैठक में विस्तृत चर्चा हुई है। इसके बाद लिए गए निर्णय के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यह निर्देश दिए गए कि अधिछात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत यूजीसी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा शिष्यवृत्ति के मानदंड तय किए जाएं। इसमें विद्यार्थियों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा कर शेष अनुदान वितरित करने की प्रक्रिया को शामिल किया जाए और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाए।

शिष्यवृत्ति प्रदान करते समय प्रत्येक घटक के लिए लाभार्थियों की संख्या निर्धारित करने संबंधी नीतिगत निर्णय लिया जाएगा। साथ ही, किस शैक्षणिक स्तर पर कितने विद्यार्थियों को लाभ दिया जाए, इस बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे। शिष्यवृत्ति योजनाओं का लाभ अधिकाधिक जरूरतमंद और वंचित वर्गों के विद्यार्थियों तक पहुंचाना ही महायुति सरकार का मुख्य उद्देश्य है। शिष्यवृत्ति मंजूर करते समय संबंधित पाठ्यक्रमों का राज्य और समाज के विकास में योगदान, विद्यार्थियों की गुणवत्ता और उनकी आर्थिक स्थिति का गहन विचार किया जा रहा है, ऐसा भी उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा। उन्होंने कहा, मैं किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मेरे काम की शैली सभी को ज्ञात है। समाज के वंचित वर्गों के वे विद्यार्थी, जिनके माता-पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर है लेकिन जो मेरिट में हैं, उन्हें सहायता देना महायुति सरकार की प्राथमिकता है। सरकार उन्हें सहायता करती है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि संबंधित संस्थाओं को ३० मार्च तक यथाशीघ्र निधि वितरित करने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही शेष निधि को भी नियमित बजट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

बीड जिले में अब तक ७ लाख क्विंटल से अधिक चीनी का उत्पादन

बीड (रिपोर्टर)

बीड जिले में इस समय आठ सहकारी चीनी मिलें कार्यरत हैं। इन मिलों द्वारा अब तक १२ लाख ६१ हजार ८४४ टन गन्ने की पेराई की जा चुकी है, जिससे ७ लाख ८६ हजार ४२० क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है। जिले में चीनी रिकवरी (उतारा) ६.२३ प्रतिशत दर्ज की गई है।

पिछले वर्ष गन्ने की खेती कम क्षेत्र में की गई थी, जिसके कारण चालू वर्ष में जिले में चीनी उत्पादन कम रहने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि, अगले वर्ष गन्ने की बुवाई का रकबा बढ़ने की संभावना है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होने की उम्मीद है।

राज्य में १ नवंबर से चीनी मिलों का सत्र शुरू हुआ है। अधिकांश सहकारी चीनी मिलों में हार्वेस्टर मशीनों के माध्यम से गन्ने की कटाई की जा रही है, जिससे कटाई का काम तेजी से हो रहा है। आने वाले वर्षों में हार्वेस्टर की संख्या में बड़े पैमाने पर वृद्धि होने की संभावना है।

राज्य में गन्ने की सबसे अधिक खेती पश्चिम महाराष्ट्र में होती है, इसी कारण उस क्षेत्र में चीनी उत्पादन भी अधिक मात्रा में होता है। बीड जिले में इस वर्ष आठ चीनी मिलें शुरू हुई हैं। इन मिलों ने अब तक १२ लाख ६१ हजार ८४४ टन गन्ने की पेराई कर ७ लाख ८६ हजार ४२० क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है, जबकि चीनी रिकवरी ६.२३ प्रतिशत रही है।

राजस्व विभाग में 'दक्षता पथकें' स्थापित, अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतों की होगी तत्काल जांच

राजस्व कार्य में पारदर्शिता लाने का निर्णय

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने राजस्व विभाग के कार्य में अधिक पारदर्शिता लाने और नागरिकों का विश्वास बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ गौण खनिज, जमीन, मुद्रांक, जमीन मोजणी और अन्य राजस्व कार्य से संबंधित प्राप्त होने वाली गंभीर शिकायतों की निष्पक्ष जांच करने के लिए अब विभागीय आयुक्त स्तर पर दक्षता पथकें स्थापित करने का शासन निर्णय (दिनांक ०४/१२/२०२५) राजस्व एवं वन विभाग ने जारी किया है। इस निर्णय से प्रशासन की विश्वसनीयता बढ़ने में मदद मिलेगी तथा अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा।

ऐसी होगी दक्षता पथक की रचना :-

प्रत्येक विभागीय आयुक्त कार्यालय के स्तर पर स्थापित की जाने वाली इन दक्षता पथकों के प्रमुख अपर आयुक्त (महसूल) होंगे। यह पथक विभिन्न विभागों के अनुभवी अधिकारियों से बना होगा। इन दक्षता पथकों को राज्य सरकार द्वारा निदेशित की गई विशिष्ट शिकायतों की जांच करनी होगी। जांच प्रक्रिया को तेज एवं प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित कार्यपद्धति निर्धारित की गई है:

जांच की अवधि: दक्षता पथकों को जांच रिपोर्ट ३० दिनों के भीतर प्रस्तुत करना बंधनकारक है।

गंभीर शिकायतें: यदि शिकायत गंभीर स्वरूप की है तो केवल १५ दिनों के भीतर प्राथमिक जांच रिपोर्ट आवश्यक सिफारिशों सहित सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

अनुशासनात्मक कार्रवाई: प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी दोषी लोकसेवकों के खिलाफ महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ के अनुसार उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकेंगे।

कडा के बंधारे की घोर उपेक्षा!

कडा (रिपोर्टर) आष्टी तालुका अंतर्गत कडा स्थित कोल्हापुरी बंधारे की हालत दिन-ब-दिन बेहद खराब होती जा रही है। प्रशासन की लापरवाही के कारण ग्रामवासियों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। १५ सितंबर को आई बाढ़ में इस बंधारे को भारी नुकसान हुआ था। दरवाजों से भारी रिसाव, संरचना में दरारें और ऊपर से गुजरने वाले रास्ते का पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होना सामने आया है। इसके बावजूद घटना को तीन महीने बीत जाने के बाद भी संबंधित विभाग ने एक बार भी वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण नहीं किया। केवल नाममात्र की जुगाडू मरम्मत कर इस गंभीर समस्या को टालने का प्रयास किया गया।

ग्रामवासियों ने लिखित शिकायतें दीं और बार-बार अनुरोध किए, लेकिन अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। बंधारे पर स्थित मुख्य मार्ग कडा-सुंदरनगर क्षेत्र को जोड़ने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण रास्ता है। यह मार्ग पिछले तीन महीनों से बंद होने के कारण किसानों को खेतों तक पहुंचने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। इससे उनकी मेहनत, समय और खर्च सभी दोगुने हो गए हैं। तीन महीने बीत गए, लेकिन एक भी जिम्मेदार अधिकारी निरीक्षण के लिए नहीं आया, ऐसा

आक्रोश ग्रामवासियों ने व्यक्त किया।

बंधारे के दरवाजे अत्यंत खराब स्थिति में होने के कारण उसमें पानी का संग्रह नहीं हो पा रहा है। लगातार रिसाव जारी है, जिससे बंधारे का मूल उद्देश्य-जलसंग्रह और कृषि के लिए पानी की उपलब्धता-खतरे में पड़ गया है। किसानों का कहना है कि यदि जल्द मरम्मत नहीं की गई तो आगामी मौसम में पानी की कमी से गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। ग्रामवासियों के जीवन और खेती के भविष्य से खिलवाड़ होना एक गंभीर विषय है, और अधिकारियों की चुप्पी व उपेक्षा अत्यंत आक्रोशजनक है।

लगातार हो रही उपेक्षा के कारण समस्या सुलझने के बजाय और गंभीर होती जा रही है। अब भी क्या संबंधित विभाग जागेगा और ठोस निर्णय लेगा? यह सवाल हर ओर उठाया जा रहा है। ग्रामवासियों की मांग है कि कोल्हापुरी बंधारे की मरम्मत का काम तुरंत शुरू किया जाए, मार्ग को यातायात के लिए खोला जाए, रिसाव को रोका जाए और भविष्य के जलसंचय को सुरक्षित किया जाए। जलसंधारण विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन न उठाए जाने के कारण उनका पक्ष ज्ञात नहीं हो सका।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com